

## उत्तराखण्ड की यूसीसी मसौदा रिपोर्ट

### प्रलिस के लिये :

[समान नागरिक संहिता \(UCC\)](#), मौलिक अधिकार, राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत

### मेन्स के लिये:

समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [समान नागरिक संहिता \(UCC\)](#) मसौदा रिपोर्ट को उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे अधिनियमन के लिये विधायक के रूप में 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

- UCC मसौदा समिति का नेतृत्व [सर्वोच्च न्यायालय](#) के सेवानिवृत्त न्यायाधीश [रंजना प्रकाश देसाई](#) ने किया।
- UCC उत्तराखण्ड के सभी नविसयों, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो, के लिये सामान्य कानूनों का एक प्रस्तावित सेट है।

### नोट:

- [भारतीय संविधान](#) का [अनुच्छेद 162](#) स्पष्ट करता है कि किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक वसित है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून निर्माण की शक्ति है। [सातवीं अनुसूची](#) की [समवर्ती सूची की प्रवर्षि 5 के प्रावधानों](#) को ध्यान में रखते हुए, समान नागरिक संहिता (UCC) को क्रियान्वित तथा कार्यान्वित करने के लिये एक समिति के गठन को अधिकार क्षेत्र से बाहर के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  - [समवर्ती सूची की प्रवर्षि 5](#) "विवाह और तलाक" शिशु तथा नाबालग; दत्तक ग्रहण, वसीयत, नरिवसीयत एवं उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार व विभाजन से संबंधित है, सभी मामले जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाही में पक्ष इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले उनके व्यक्तिगत कानून के अधीन थे।
- इसका अर्थ यह है कि [उत्तराखण्ड राज्य सरकार अपने क्षेत्र के भीतर UCC अधिनियमि कर सकती है।](#)

## उत्तराखण्ड की UCC मसौदा रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- UCC का लक्ष्य संविधान के [अनुच्छेद 44](#) द्वारा निर्देशित, विवाह, तलाक, दत्तक और वरिसत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हर धर्म के अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को बदलना है।
  - संविधान [अनुच्छेद 44](#), [राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्व \(DPSP\)](#) है। इसमें कहा गया है कि राज्य को संपूर्ण भारत में सभी नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये।
  - यह मसौदा [व्यक्तिगत कानूनों का एक एकल सेट](#) होगा जो सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।
- समिति द्वारा पेश किये गए कुछ प्रमुख प्रस्तावों में [बहुविवाह](#), [इलाल](#), इदत (मुस्लिम विवाह के वधितन के बाद महिलाओं द्वारा की जाने वाली प्रतीक्षा की अनिवार्य अवधि), [तीन तलाक](#) एवं [बाल विवाह](#) पर प्रतिबंध, लड़कियों के लिये समान उम्र के साथ ही [सभी धर्मों में विवाह तथा लवि-इन संबंधों का अनिवार्य पंजीकरण](#) शामिल हैं।
- UCC के मसौदे का उद्देश्य वरिसत तथा विवाह जैसे मामलों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करके [लैंगिक समानता](#) पर ध्यान केंद्रित करना है।
  - इस मसौदे में [मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत प्राप्त मौजूदा 25% हस्सेदारी के मुकाबले समान संपत्ति](#)

हसिसेदारी का वसितार करने की भी संभावना है।

○ पुरुषों और महिलाओं के लयि वविाह की न्यूनतम आयु एक समान रखी गई है, महिलाओं के लयि 18 वर्ष एवं पुरुषों के लयि 21 वर्ष है।

- अनुसूचति जनजाति (ST) को इस वधियक के दायरे से बाहर रखा गया है। राज्य में आदविसी आबादी जो लगभग 3% है, उन्हें दयि गए वशिष दरजे के कारण UCC के खलिाफ अपना असंतोष व्यक्त कर रही थी।

## उत्तराखंड की UCC मसौदा रपिर्ट के संबंध में क्या चतिाएँ हैं?

- UCC मसौदा रपिर्ट भारत के संवधिान द्वारा गारंटीकृत धारमकि स्वतंत्रता तथा वैयक्तकि स्वतंत्रता के मौलकि अधकिारों का उल्लंघन कर सकती है।
  - कुछ आलोचकों का तर्क है कि UCC मसौदा रपिर्ट भारत की वविधिता तथा बहुलवाद के अनुरूप नहीं है एवं एक समान संहतिा कार्यान्वति करने का प्रावधान है जो वभिनिन समुदायों के रीत-रिवाजों और प्रथाओं के अनुरूप नहीं हो सकती है।
- यूसीसी ड्राफ्ट रपिर्ट से उत्तराखंड के ST के अधकिारों और हतियों पर असर पड़ सकता है।
  - कुछ कार्यकरत्ताओं का दावा है कि UCC मसौदा रपिर्ट ST के मुद्दों और आकांक्षाओं को पर्याप्त रूप से संबोधति नहीं करती है तथा उनकी सांस्कृतकि पहचान एवं स्वायत्तता को नष्ट कर सकती है।

## समान नागरकि संहतिा क्या है?

- परचिय:
  - समान नागरकि संहतिा का उल्लेख भारतीय संवधिान के अनुच्छेद 44 में कयिा गया है, जो राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।
    - हालाँकि संवधिान नरिमाताओं ने UCC को लागू करने का कार्य सरकार के वविक पर छोड़ दयिा था।
  - गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरकि संहतिा लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारविरकि कानून को बनाये रखा, जसिे गोवा नागरकि संहतिा (Goa Civil Code) के रूप में जाना जाता है।
- UCC पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख:
  - मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (वर्ष 1985) मामला:
    - न्यायालय ने कहा कि "यह अफसोस की बात है कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बनकर रह गया है" और इसके कार्यान्वयन का आह्वान कयिा।
    - इस तरह की मांग बाद के मामलों जैसे [?/?/?/?] [?/?/?/?/?] [?/?/?/?] [?/?/?/?] [?/?/?], 1995 और [?/?/?] [?/?/?/?/?/?/?/?/?/?] [?/?/?/?] [?/?/?/?] [?/?/?], 2003 में दोहराई गई थी।
- वधिआयोग का रुख:
  - वर्ष 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बलबीर सहि चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें वधिआयोग ने "पारविरकि वधिा में सुधार" पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत कयिा, जसिमें यह माना गया कि "इस स्तर पर समान नागरकि संहतिा का नरिमाण न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय"।
    - इसने रेखांकति कयिा कि धर्मनरिपेक्षता को देश में प्रचलति बहुलता के साथ सह-असततिव में रहना चाहयिे। हालाँकि इसने सफिरशि की कि मौजूदा व्यक्तगित कानूनों/परसनल लॉ के भीतर भेदभावपूर्ण प्रथाओं तथा रूढविादतिा में संशोधन कयिा जाना चाहयिे।
  - प्रारंभकि परामर्श पत्र जारी होने के बाद तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने को स्वीकार करते हुए वर्ष 2022 में, न्यायमूर्ति (सेवानवृत्त) ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें वधिआयोग ने एक अधसूचना जारी कर UCC पर सार्वजनकि और धारमकि संगठनों सहति वभिनिन हतिधारकों से राय मांगी।

और पढ़ें: [न्यायपूर्ण \(समान\) नागरकि संहतिा](#)

## वधिकि दृष्टकिेण:

[समान अधकिार, कानून नहीं](#)

<https://www.drishtijudiciary.com/hin/>

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

भारतीय संविधान में प्रतष्टिठापति राज्य की नीतके नदिशक तत्त्वों के अंतरगत नमिनलखिति प्रावधानों पर वचिर कीजयि: (2012)

1. भारतीय नागरकों के लयि समान नागरकि (सविलि) संहति सुरक्षति करना
2. ग्राम पंचायतों को संघटति करना
3. ग्रामीण कषेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहति करना
4. सभी श्रमकों के लयि उचति अवकाश और सांस्कृतकि अवसर सुरक्षति करना

उपर्युक्त में से कौन-से गांधीवादी सदिधांत हैं, जो राज्य की नीतके नदिशक तत्त्वों में प्रतबिबिति होते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. कानून को लागू करने के मामले में कोई वधिान, जो कसिी कार्यपालक अथवा प्रशासनकि प्राधिकारी को अनरिदेशति एवं अनरिर्तृरति वविकाधकिार देता है, भारत के संविधान के नमिनलखिति अनुच्छेदों में से कसिका उल्लंघन करता है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 14
- (b) अनुच्छेद 28
- (c) अनुच्छेद 32
- (d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (a)

**??????:**

प्रश्न. चर्चा कीजयि कविे कौन-से संभावति कारक हैं जो भारत को राज्य की नीतके नदिशक तत्त्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरकों के लयि समान सविलि संहति को अभनियिमति करने से रोकते हैं। (2015)